भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2773
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **धान के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बोनस**

2773. एडवोकेट अद्वूर प्रकाशः
श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने केरल सरकार को धान के किसानों को दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर अतिरिक्त बोनस को बंद करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राज्य में धान की खेती में लगातार गिरावट आ रही है और धान के किसान खेती जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं;

(ग) क्या एमएसपी बोनस बंद करने के कदम से स्थिति और खराब हो जाएगी और यदि हां, तो क्या सरकार केरल राज्य को इस संबंध में छूट प्रदान करेगी;

(घ) उन राज्यों की संख्या और ब्यौरा क्या है जहाँ धान और गेहूं के लिए एमएसपी के ऊपर अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाता है; और

(ङ) केरल राज्य में धान की खेती की विकास दर का ब्यौरा क्या है और क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): व्यय सचिव द्वारा राज्य के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 9 जनवरी 2026 के पत्र में राज्य सरकारों को अपनी बोनस नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे।

केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल सरकार का धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक प्रोत्साहन बोनस प्रदान करने की वर्तमान नीति की समीक्षा करने या उसे वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के लिए धान पर और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2025-26 के लिए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक बोनस घोषित किया है।

केरल में चावल उत्पादन में वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव का रुझान देखा गया है। वर्ष 2021-22 में उत्पादन 4.87 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.96 लाख टन हो गया और फिर वर्ष 2023-24 में घटकर 4.98 लाख टन रह गया और उसके बाद वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5.16 लाख टन हो गया।

*****